संख्या 15011/36/2022-जेयूएस (एयू)/ई6889
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: **न्याय विभाग से संबंधित जून, 2022 माह का मासिक सार।**

न्याय विभाग से संबंधित जून, 2022 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022**:
विभाग ने जैसलमेर हाउस, हेरिटेज बिल्डिंग स्थित अपने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। विभाग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 के निर्बाध संचालन के लिए न्यायपालिका के निकट संपर्क में भी था। इस समारोह को अप्रत्याशित रूप से बड़े पैमाने पर मनाया गया जिसमें उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों,जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायपालिका अधिकारियों, न्यायालय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों और विभिन्न न्यायालय परिसरों में स्थित बार सदस्यों सहित 30,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अद्वितीय वास्तुकला वाली प्रतिष्ठित इमारतों में स्थित उच्च न्यायालयों ने इस अवसर की भव्यता में चार चांद लगाया। सामान्य योग प्रोटोकॉल, विशेषज्ञ द्वारा विभिन्न योग आसनों के लाभां की जागरूकता और योगाभ्यास इस समारोह में की गई कुछ गतिविधियों में से थीं।

2. **ईकोर्ट मिशन मोड परियोजना फेज-।।:**
- **वाइड एरिया नेटवर्क:** 2992 कोर्ट परिसरों में से 2970 कोर्ट परिसरों में 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के नेटवर्क चालू किए गए।
- **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी):** ई कोर्ट सर्विस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वादीगण इन कंप्यूटरीकृत न्यायालय से संबंधित दिनांक 1 जून, 2022 तक के 20.63 करोड़ से अधिक मामलों और 17.77 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की स्थिति से संबंधित सूचना हासिल कर सकते हैं।
- **वर्चुअल कोर्ट:** वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 1.59 करोड से अधिक मामलों को निपटाया गया और 25 लाख से अधिक मामलों में 258 करोड़ अधिक (258.28) रुपए का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया।
- **ईतालः** इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन एकीकरण एवं विश्लेषण लेयर (ई ताल) पोर्टलपर प्रकाशित डाटा के अनुसार, ई कोर्ट भारत में पांच शीर्ष मिशन मोड परियोजनाओं में एक अग्रणी परियोजना है जिसके माध्यम से पिछले 1 वर्ष में कुल 514 करोड़ लेनदेन किए गए हैं।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगः**लॉकडाउन अवधि प्रारंभ होने से लेकर दिनांक 30 जून, 2022 तक उच्चतम न्यायालय में 2,61,338 मामलों की सुनवाई की गई।
- **ओडिशा उच्च न्यायालय अपने स्वयं के कार्य निष्पादन का आकलन करता है:** ओडिशा उच्च न्यायालय ने 2021 में अपने कार्य निष्पादन की एक विशेष तरह की वार्षिक रिपोर्ट पेश की है जिसमें राज्य में उच्च न्यायालय और निचली न्यायपालिका के कार्य निष्पादन की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने के लिए अपने स्वयं के परिसर में और प्रत्येक जिला अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग केबिन उपलब्ध कराए हैं।

3. टेली लॉः वंचितों तक पहुंच:

30 जून, 2022 तक पिछले माह के दौरान 1,09,144 लाभार्थियों सहित कुल 20,20,931 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई।

टेली लॉ कार्यक्रम पर पैनल वकीलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए और न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएं) लागू करने के लिए और एक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए कानूनी सेवाओं की एकीकृत प्रदाएगी पर न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वीएलई/पीएलवी, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा आयोजित 161 प्रशिक्षण और जागरूकता सत्रों/कैंपों में 4957 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

4. (प्रो बोनो लीगल सर्विस) कार्यक्रमः

क) माह के दौरान, 138 नए प्रो बोनो वकीलों ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया। न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल पर अब तक कुल 4354 वकील (पुरुष-3789, महिला 563, ट्रांसजेंडर-02) पंजीकृत हो चुके हैं।

ख) उच्च न्यायालयों में न्याय बंधु पैनल के तहत 27 नए वकीलों ने नामांकन किया। अब तक उच्च न्यायालयों में न्याय बंधु पैनल के तहत 25 उच्च न्यायालयों में से 19 उच्च न्यायालयों के कुल 818 प्रो बोनो वकीलों ने नामांकन किया है।

ग) 49 विधि विद्यालयों ने अपने संबंधित विधि विद्यालयों/कॉलेजों में अब तक प्रो बोनो क्लब स्कीम के अंतर्गत प्रो बोनो क्लब प्रारंभ किए हैं।

5. **कानूनी साक्षरता कार्यक्रम** :

क) कानूनी जागरूकता वेबीनार श्रंखला के भाग के रूप में,

न्याय विभाग ने 29 जून 2022 को **"भारत में मानव तस्करी"** विषय पर अपनी नौ वीं मासिक वेबीनार आयोजित की। पुलिस, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सिक्किम, राज्य महिला आयोग और शक्ति वाहिनी के प्रमुख वक्ताओं ने संवैधानिक और व्यवहारिक विचारों का आदान प्रदान किया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब दिया। इस वेबीनार के माध्यम से 15809 प्रतिभागियों तक पहुंचा गया।

ख) सिक्किम राज्य महिला आयोग (एसएससी डब्लू) ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 और यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम पर एक दिवसीय कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्यालसिंग,सिक्किम के 850 अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया।

ग) शैडो एडवरटाइजिंग भुवनेश्वर उड़ीसा ने उड़ीसा के ढेंकानाल जिले के कैमाटी, सिमिलिया और भगवानपुर गांव में **"बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार"** पर तीन नुक्कड़ नाटक आयोजित किए। इन नुक्कड़ नाटकों में 310 ग्राम वासियों ने भाग लिया।

xxxxxxxxxxxx